वैभव के डेब्यू को लेकर श्रेयस अय्यर ने कहा- टीम के खिलाड़ियों का समर्थन जरूरी

Page-04

tv भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

रणवीर कपूर और यश ने दिखाई रामायण फिल्म की झलक

Page-05

जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सौंपी सेना की कमान

भारतीय सेना में नेतृत्व परिवर्तन के महत्वपूर्ण अवसर पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चार दशक से अधिक लंबे सैन्य जीवन के बाद अपना पदभार जनरल धीरज सेठ को सौंप दिया। इस अवसर पर आयोजित विदाई समारोह में जनरल द्विवेदी ने अपने सैन्य जीवन को याद करते हुए कहा कि भारतीय सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान और सौभाग्य रहा है। उन्होंने सैनिकों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सेना की वास्तविक शक्ति उसके जवानों और देश के नागरिकों के विश्वास में निहित है।पदभार छोड़ने से पहले जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल से शुरु हुई उनकी यात्रा भारतीय सेना के सर्वोच्च पद तक पहुंची, जो उनके लिए गर्व और संतोष का विषय है। उन्होंने उन सभी वीर सैनिकों को नमन किया जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया।विदाई संबोधन में उन्होंने कहा कि सेना की उपलब्धियां किसी एक व्यक्ति की नहीं होतीं, बल्कि यह सामूहिक नेतृत्व, अनुशासन, प्रशिक्षण और जवानों की प्रतिबद्धता का परिणाम होती हैं। उन्होंने अधिकारियों और सैनिकों से भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ देश सेवा जारी रखने का आह्वान किया। उनके अनुसार भारतीय सेना हमेशा बदलती चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रही है और भविष्य में भी अपनी पेशेवर क्षमता को और मजबूत बनाएगी।जनरल धीरज सेठ ने पदभार संभालने के बाद पूर्व सेना प्रमुख के योगदान की सराहना की और कहा कि वह भारतीय सेना की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक सैन्य क्षमताओं को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने जवानों के मनोबल, प्रशिक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही।

सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने E20 पेट्रोल पर रखा पक्ष

कहा- अगले वर्ष तक और स्पष्ट होंगे नतीजे

देश में इथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा देने की नीति के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण (E20) का कार्यक्रम अभी परीक्षण और मूल्यांकन के चरण में है। सरकार ने अदालत को बताया कि इस योजना के दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन लगातार किया जा रहा है और अगले वर्ष तक इसके परिणाम अधिक स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगे। सरकार का कहना है कि फिलहाल उपलब्ध वैज्ञानिक और तकनीकी आंकड़ों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि E20 पेट्रोल से वाहनों के मैकेनिकल पार्ट्स को नुकसान पहुंचता है।E 2 0 पेट्रोल को लेकर देशभर में लंबे समय से बहस चल रही है। कई वाहन मालिकों और विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि अधिक इथेनॉल मिश्रण से विशेषकर पुराने वाहनों के इंजन, फ्यूल पाइप और अन्य पुर्जों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही कुछ लोगों ने ईंधन दक्षता में कमी आने की भी चिंता व्यक्त की है। इन्हीं मुद्दों को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना विस्तृत पक्ष रखा।सरकार ने कहा कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन का उद्देश्य केवल पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करना नहीं है, बल्कि इससे किसानों की आय बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। देश में गन्ना और अन्य कृषि उत्पादों से बनने वाले इथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देने से घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी।सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि वाहन निर्माता कंपनियां धीरे-धीरे E20 अनुकूल इंजन विकसित कर रही हैं। नई पीढ़ी के अधिकांश वाहनों को इस ईंधन के अनुरूप तैयार किया जा रहा है, जबकि पुराने वाहनों के संबंध में भी तकनीकी अध्ययन जारी हैं। आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में नीति में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं।विशेषज्ञों का मानना है कि E20 नीति भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है, लेकिन इसके सफल क्रियान्वयन के लिए वाहन उद्योग, तेल कंपनियों और उपभोक्ताओं के बीच बेहतर समन्वय जरूरी होगा। फिलहाल सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और आधिकारिक तकनीकी रिपोर्टों पर भरोसा करने की अपील की है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की आगे की सुनवाई और सरकार की विस्तृत रिपोर्ट पर सभी की नजर बनी हुई है।

लोहागढ़ किले में बढ़ा 'डार्क टूरिज्म' हत्याकांड जगह देखने पहुंच रहे पर्यटक

महाराष्ट्र के पुणे जिले में लोनावला के निकट स्थित करीब दो हजार वर्ष पुराने ऐतिहासिक लोहागढ़ किले की पहचान अब केवल उसके गौरवशाली इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं रह गई है। हाल ही में चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड के बाद यह किला एक नए कारण से सुर्खियों में है। रिपोर्टों के अनुसार, इस घटना के बाद यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बड़ी संख्या में लोग किले के ऐतिहासिक महत्व को देखने के बजाय उस स्थान को देखने पहुंच रहे हैं, जहां कथित तौर पर अपराध को अंजाम दिया गया था।पर्यटन विशेषज्ञ इस प्रवृत्ति को 'डार्क टूरिज्म' का हिस्सा मान रहे हैं। डार्क टूरिज्म उस प्रकार के पर्यटन को कहा जाता है, जिसमें लोग किसी दुर्घटना, अपराध, युद्ध या अन्य दुखद घटनाओं से जुड़े स्थानों को देखने के लिए जाते हैं। दुनिया के कई देशों में ऐसी जगहें पहले से ही पर्यटकों को आकर्षित करती रही हैं, लेकिन भारत में इस तरह की घटनाएं अपेक्षाकृत कम देखने को मिलती हैं।स्थानीय लोगों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में किले पर आने वाले कई पर्यटक सबसे पहले उस कथित स्थान के बारे में जानकारी मांगते हैं, जहां हत्याकांड से जुड़ी घटना हुई थी। इसके कारण गाइडों और प्रशासन को भी लगातार लोगों के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे ऐतिहासिक धरोहर का सम्मान करें और अफवाहों या अपुष्ट जानकारियों के आधार पर किसी स्थान को सनसनीखेज तरीके से प्रस्तुत न करें।

ट्रंप की नीतियों को ठहराया रिश्तों में तनाव का जिम्मेदार

भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि दोनों देशों के रिश्ते पिछले तीन दशकों के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। वॉशिंगटन में आयोजित यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद ने मौजूदा हालात के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।रो खन्ना ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच वर्षों से रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग लगातार मजबूत होता रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में कई मुद्दों पर दोनों देशों के संबंधों में तनाव देखने को मिला है। उनके अनुसार यह स्थिति दोनों देशों के दीर्घकालिक हितों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोई इस बात पर संदेह करता है तो भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से भी इस विषय पर चर्चा की जा सकती है।अपने संबोधन में खन्ना ने कहा कि वह राजनीतिक शिष्टाचार के नाम पर वास्तविकता छिपाने में विश्वास नहीं रखते। उनका मानना है कि मजबूत साझेदारी तभी संभव है जब दोनों देश एक-दूसरे के हितों और चिंताओं को समान महत्व दें। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था, आर्थिक विकास, तकनीकी सहयोग और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण साझेदार हैं।रो खन्ना ने दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा सहयोग, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को कमजोर नहीं होने देना चाहिए।हालांकि ट्रंप प्रशासन या अमेरिकी सरकार की ओर से रो खन्ना के बयान पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका में आगामी राजनीतिक परिस्थितियों और वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत-अमेरिका संबंधों पर ऐसे बयान चर्चा का विषय बने रहेंगे।विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग आने वाले समय में भी वैश्विक राजनीति का महत्वपूर्ण आधार रहेगा। ऐसे में राजनीतिक मतभेदों के बावजूद संवाद और सहयोग को बनाए रखना दोनों देशों के साझा हित में माना जा रहा है।

17 साल बाद RMO का तबादला

अयोध्या स्थित राम मंदिर में दान राशि की कथित चोरी के मामले की जांच लगातार तेज होती जा रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में लगभग 17 वर्षों से अयोध्या में तैनात रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर (RMO) अर्जुन देव का तबादला गोरखपुर कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच को निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक निर्णय लिए जा रहे हैं।जांच एजेंसियों के अनुसार, अब तक गिरफ्तार किए गए सभी आठ आरोपियों को अदालत ने 14 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस दौरान जांच दल आरोपियों से पूछताछ के अलावा बैंक लेनदेन, सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेजों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी गहन जांच कर रहा है। अधिकारियों का मानना है कि मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य अभी सामने आना बाकी हैं। सूत्रों के मुताबिक, जांच का दायरा अब काफी विस्तृत कर दिया गया है। बैंक अधिकारियों, मंदिर प्रशासन से जुड़े कर्मचारियों, दान राशि की गिनती और जमा प्रक्रिया में शामिल लोगों सहित लगभग 80 व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि दान राशि के प्रबंधन में कहीं कोई प्रशासनिक लापरवाही, प्रक्रियागत कमी या किसी प्रकार की मिलीभगत तो नहीं हुई।

सचिन अहीर के शिवसेना में आने पर शिंदे का तंज

महाराष्ट्र की राजनीति में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला, जब वरिष्ठ विधान परिषद सदस्य सचिन अहीर ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थाम लिया। इसके साथ ही उन्होंने महायुति गठबंधन की ओर से विधान परिषद के उपसभापति पद के लिए अपना नामांकन भी दाखिल किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहीर का स्वागत करते हुए उनके राजनीतिक फैसले को क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के 'मास्टरस्ट्रोक' से जोड़ते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा।एकनाथ शिंदे ने कहा कि सचिन अहीर का यह फैसला राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सचिन तेंदुलकर मैच की दिशा बदल देने वाले शॉट खेलते थे, उसी तरह अहीर ने भी सही समय पर बड़ा राजनीतिक निर्णय लिया है। शिंदे ने दावा किया कि उनकी पार्टी किसी को तोड़ने की राजनीति नहीं करती, बल्कि समान विचारधारा वाले

नेताओं को साथ लेकर संगठन को मजबूत बनाने में विश्वास रखती है।उन्होंने कहा कि महायुति गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है और विभिन्न दलों के अनुभवी नेता विकास की राजनीति से प्रभावित होकर गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। शिंदे ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल सत्ता चलाना नहीं, बल्कि राज्य के विकास को नई गति देना है। ऐसे में अनुभवी नेताओं का साथ मिलना गठबंधन के लिए सकारात्मक संकेत है।सचिन अहीर लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और विभिन्न दलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। उनके शिवसेना में शामिल होने को आगामी राजनीतिक रणनीतियों और विधान परिषद की कार्यवाही के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे महायुति गठबंधन की स्थिति और मजबूत हो सकती है।

हिन्दी जगत महामंच

www.tvbharatvarsh.in

tv भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक ई-पेपर

प्रदेश का नं. 1

प्रतिष्ठित हिन्दी न्यूज़ ई-पेपर

विज्ञापन दर

साईज	विजिटिंग कार्ड	क्वाटर पेज	हाफ पेज	फुल पेज (अंदर)	फुल पेज (कवर 2-3)	फुल पेज (कवर 4- अंतिम)	(फ्रंट पेज)
रेट	₹ 3000	₹ 6000	₹ 10,000	₹ 20,000	₹ 25,000	₹ 30,000	₹ 100000

8601780000

मानव संसाधन गतिशीलता पर जयशंकर का जोर, कहा- दुनिया तेजी से बदल रही है

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में कुशल मानव संसाधन की मांग बढ़ रही है। भारत सुरक्षित, कानूनी प्रवासन, डिजिटल व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है।

नई दिल्ली में आयोजित मानव संसाधन गतिशीलता मंच को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलती व्यवस्था में कौशल आधारित मानव संसाधन की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकीय बदलाव, तकनीकी नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन, डिजिटलीकरण और हरित अर्थव्यवस्था जैसी नई प्रवृत्तियां वैश्विक श्रम बाजार को नया स्वरूप दे रही हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य, विनिर्माण, निर्माण और कृषि जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में भी कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता बनी हुई है। ऐसे समय में देशों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह रचनात्मक सोच और सहयोग के माध्यम से भविष्य की समृद्धि सुनिश्चित करें। विदेश मंत्री ने कहा कि लंबे समय तक वैश्विक आर्थिक चर्चाएं व्यापार, निवेश और पूंजी के प्रवाह तक सीमित रही थीं, लेकिन अब मानव संसाधन आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार बनकर उभरा है। दुनिया के अनेक देश यह समझने लगे हैं कि सतत विकास, नवाचार और उत्पादकता बनाए रखने के लिए कुशल और अनुकूलनशील प्रतिभा तक पहुंच अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन गतिशीलता केवल लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का विषय नहीं है, बल्कि यह आकांक्षाओं को अवसरों से जोड़ने, प्रतिभा को मांग से मिलाने और आर्थिक प्रगति के नए रास्ते तैयार करने की प्रक्रिया है। इसके माध्यम से आर्थिक विकास के साथ सामाजिक कल्याण को भी मजबूती मिलती है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की दृष्टि केवल विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत मानव संसाधन गतिशीलता को अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की साझेदारियां पारस्परिक लाभ, साझा जिम्मेदारी और दीर्घकालिक स्थिरता पर आधारित होती हैं। यदि इन्हें प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए तो इससे स्रोत देशों, गंतव्य देशों, नियोक्ताओं, श्रमिकों और समाज सभी को लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित, व्यवस्थित और कानूनी प्रवासन सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग अत्यंत आवश्यक है। भारत अब तक 26 देशों के साथ 28 प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते कर चुका है, जबकि कई अन्य देशों के साथ बातचीत जारी है। विदेश मंत्री ने अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी और शोषणकारी बिचौलियों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां कानूनी प्रवासन व्यवस्था की विश्वसनीयता को कमजोर करती हैं और कमजोर वर्गों को जोखिम में डालती हैं। उन्होंने बताया कि प्रवासन प्रबंधन में डिजिटल व्यवस्था ने महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। दो वर्ष पहले शुरू किए गए ई माइग्रेट संस्करण-2 मंच ने प्रवासन प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और कानूनी बनाया है। विदेश मंत्री के अनुसार इस मंच के माध्यम से अब तक पचास लाख से अधिक प्रवासन स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि यह डिजिटल व्यवस्था तकनीक के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वैश्विक उदाहरण बन चुकी है। ष्ट्रीय सहयोग को नई शक्ति प्रदान कर सकती है।

नाटो ने रक्षा तैयारियों पर बढ़ाया जोर, यूरोप में सुरक्षा रणनीति की समीक्षा

रूस-यूक्रेन युद्ध के लगातार जारी रहने के बीच नाटो सदस्य देशों ने अपनी सामूहिक सुरक्षा तैयारियों को और मजबूत करने का फैसला किया है। संगठन के सदस्य देशों ने रक्षा खर्च बढ़ाने, सैन्य समन्वय मजबूत करने और पूर्वी यूरोप में सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा पर जोर दिया है। इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती, रसद व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को बेहतर बनाने के लिए भी कई नई योजनाओं पर विचार किया जा रहा है।हालिया बैठकों में सदस्य देशों ने आधुनिक रक्षा तकनीक, वायु सुरक्षा प्रणाली, साइबर सुरक्षा और संयुक्त सैन्य अभ्यासों को प्राथमिकता देने पर सहमति जताई। नाटो अधिकारियों का कहना है कि बदलते सुरक्षा माहौल को देखते हुए संगठन को हर संभावित चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए सदस्य देशों के बीच खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान और संयुक्त रणनीति को भी मजबूत किया जाएगा।रूस ने नाटो की इन गतिविधियों की आलोचना करते हुए कहा है कि सैन्य विस्तार से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। वहीं नाटो का कहना है कि उसके कदम पूरी तरह रक्षात्मक हैं और सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाए जा रहे हैं। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य किसी देश के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई नहीं, बल्कि सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करना है।यूरोप के कई देशों ने रक्षा उद्योग में निवेश बढ़ाने और सैन्य उपकरणों के संयुक्त उत्पादन पर भी चर्चा की है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले महीनों में यूरोप की सुरक्षा नीति और रक्षा सहयोग में और तेजी देखने को मिल सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि क्षेत्रीय तनाव इसी तरह बना रहता है, तो नाटो अपने दीर्घकालिक रक्षा ढांचे में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव कर सकता है, जिससे यूरोप की सामूहिक सुरक्षा रणनीति और अधिक सशक्त होगी।

PM Modi का 'Viksit Bharat' पर फोकस
सचिवों संग हाई लेवल मीटिंग में बनेगा Action Plan

महाराष्ट्र की राजनीति से धमाकेदार सियासी खबर

महाराष्ट्र की राजनीति से इस समय की सबसे बड़ी और धमाकेदार सियासी खबर सामने आ रही है। शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस के बीच विलय को लेकर बेहद गंभीर चर्चा शुरू हो चुकी है। इस बात की आधिकारिक पुष्टि खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता विजय वडेट्टीवार ने की है। एनडीटीवी से खास बातचीत में विजय वडेट्टीवार ने इस संभावित विलय पर मुहर लगाते हुए कहा शरद पवार की पार्टी के कांग्रेस में विलय को लेकर हमारे केंद्रीय आलाकमान के साथ बातचीत चल रही है। जो लोग भी कांग्रेस और शरद पवार की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उन सभी का हमारी पार्टी में हमेशा स्वागत है। सियासी गलियारों में इस खबर के बाद से हलचल तेज हो गई है। गौरतलब है कि साल 1999 में शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी' (NCP) का गठन किया था। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि साल 2023 में उनके भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर दी और एनसीपी को दो फाड़ कर दिया। अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ महाराष्ट्र की बीजेपी-शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे। भतीजे की बगावत के बाद शरद पवार की पार्टी (NCP-SP) महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, और अब दोनों दलों के पूरी तरह एक होने की सुगबुगाहट ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में नया उबाल ला दिया है। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे जैसे क्षेत्रीय नेताओं को हाल ही में राजनीतिक झटके लगे हैं। उनके सांसदों ने अपनी मूल पार्टियों को छोड़कर अलग गुट बनाने का फ़ैसला किया है और इसी माहौल में कांग्रेस के साथ संभावित विलय की चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक, नई दिल्ली में शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के कांग्रेस में विलय को लेकर वरिष्ठ नेतृत्व स्तर पर बातचीत अब अंतिम चरण में है और इसमें सकारात्मक प्रगति हुई है।

ईरान ने IAEA से सहयोग किया सीमित परमाणु कार्यक्रम पर बढ़ा वैश्विक तनाव

ईरान और पश्चिमी देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव एक बार फिर गहरा गया है। हाल के सैन्य संघर्षों और परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों के बाद ईरानी संसद ने एक ऐसा विधेयक पारित किया है, जिसके तहत देश का अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ सहयोग सीमित किया जा सकता है। इस कदम ने अमेरिका, यूरोपीय देशों और संयुक्त राष्ट्र के भीतर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं।ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हालिया हमलों के दौरान उनके परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं प्रभावी भूमिका नहीं निभा सकीं। उनका आरोप है कि एजेंसी की कुछ रिपोर्टों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया गया। इसी कारण अब भविष्य में निरीक्षण और सहयोग की नई शर्तें लागू की जा सकती हैं।दूसरी ओर IAEA ने स्पष्ट किया है कि उसका उद्देश्य केवल परमाणु गतिविधियों की निगरानी करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परमाणु सामग्री का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो। एजेंसी ने ईरान से अपील की है कि वह निरीक्षकों के साथ सहयोग जारी रखे और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन करे।अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित कई पश्चिमी देशों ने ईरान के फैसले पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि यदि निरीक्षण प्रक्रिया बाधित होती है तो क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने भी दोनों पक्षों से बातचीत के जरिए समाधान निकालने का आग्रह किया है।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईरान और IAEA के बीच सहयोग और कम होता है तो परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को बड़ा झटका लग सकता है। इससे मध्य-पूर्व में पहले से मौजूद अस्थिरता और बढ़ने की आशंका है। कई देशों ने कूटनीतिक संवाद जारी रखने पर जोर दिया है ताकि किसी नए सैन्य टकराव से बचा जा सके।इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं। आने वाले दिनों में IAEA बोर्ड की बैठकों, संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया और प्रमुख देशों के कूटनीतिक प्रयास तय करेंगे कि यह विवाद बातचीत के रास्ते आगे बढ़ता है या फिर क्षेत्र में तनाव और गहराता है।

ब्लैक गोल्ड की कहानी: कैसे बदल गई दुनिया

एक दिन आप सुबह-सुबह सोकर उठे देखा तो हर तरफ हड़कंप मचा था जानने की इच्छा हुई कि आखिर हुआ क्या आंख मलते हुए मोबाइल पर तुरंत न्यूज़ पढ़ी तो होश उड़ गए खबर थी कि दुनिया में कच्चा तेल खत्म यानी पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं बचा बूंद भर भी नहीं सुनकर टेंशन तो होगी घर के दरवाजे पर कार खड़ी है बाइक खड़ी है अब उनका क्या होगा लेकिन कुछ देर की टेंशन थी जो दो बातें सोचकर कम हुई पहली अरे यह दर्द केवल हमारा थोड़ी है यह तो जगत भर की समस्या है। दूसरा कोई नहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक कार्स तो मार्केट में आ गई हैं घर की लाइट और एसी वसी भी चल रहा है तेल रुकने से यह कुछ भी बंद नहीं हुआ लेकिन कुछ रोज महंगाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि कुछ समय के लिए सही देश की अर्थव्यवस्था के चक्के तो जम ही जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आपको यह लगे कि आप 170 साल पहले पहुंच गए 170 साल पहले की बात इसलिए क्योंकि तब पेट्रोल और डीजल कुछ भी इजाद नहीं हुआ था या कहिए खोजा नहीं गया था। बल्ब भी नहीं जला था, पंखा भी नहीं था और एसी भी नहीं था। लेकिन तब लोग जीते कैसे थे। क्या रात को घरों में अंधेरा ही रहता था? अगर नहीं तो रातों को घरों में रोशनी आखिर होती कैसे थी फिर केरोसिन ऑइल यानी मिट्टी के तेल की खोज कैसे हुई और फिर किसका दिमाग घूमा और दुनिया बदलने वाले पेट्रोल डीजल की खोज हुई। तो चलिए, आज ग्लोब को थोड़ा घुमाते हैं और चलते हैं इतिहास के उस दौर में... जहाँ से इंसानियत का यह 'ऑयल एडवेंचर' शुरू हुआ था। लेकिन इस 'ब्लैक गोल्ड' यानी कच्चे तेल की कहानी सिर्फ कुओं से निकलने वाले काले गाढ़े लिक्विड की नहीं है... यह कहानी है इंसानी लालच, महाशक्तियों के दबदबे और दुनिया को मुट्ठी में करने की जंग की!

संपादक की कलम से

पानी केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। इसके बिना मानव जीवन, कृषि, उद्योग और पर्यावरण की कल्पना भी संभव नहीं है। विडंबना यह है कि जिस जल को प्रकृति ने अमूल्य धरोहर के रूप में हमें सौंपा है, उसी का सबसे अधिक दुरूपयोग भी हम ही कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में हर वर्ष गर्मियों के दौरान जल संकट गंभीर रूप ले लेता है। कहीं पेयजल के लिए लंबी कतारें लगती हैं तो कहीं किसान सिंचाई के अभाव में अपनी फसलें बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। यह स्थिति स्पष्ट संकेत देती है कि यदि अभी भी जल संरक्षण को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो आने वाले वर्षों में यह संकट और विकराल हो सकता है।भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में शामिल है, जबकि मीठे जल के संसाधन सीमित हैं। बढ़ती जनसंख्या, अनियोजित शहरीकरण, भूजल का अत्यधिक दोहन, नदियों का प्रदूषण और वर्षा जल के उचित संचयन की कमी ने समस्या को और गंभीर बना दिया है। अनेक शहरों में भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। कई नदियां औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू कचरे के कारण प्रदूषित हो चुकी हैं, जिससे स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता प्रभावित हो रही है।सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। 'जल जीवन मिशन', 'अटल भूजल योजना' और वर्षा जल संचयन जैसी पहलें सकारात्मक दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। कई राज्यों में तालाबों और जलाशयों के पुनर्जीवन का कार्य भी किया जा रहा है। हालांकि, केवल सरकारी योजनाओं के भरोसे इस चुनौती का समाधान संभव नहीं है। जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति जल संरक्षण को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं मानेगा, तब तक अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। हर नागरिक अपने स्तर पर छोटे-छोटे प्रयास करके बड़ा बदलाव ला सकता है। घरों में पानी की बर्बादी रोकना, वर्षा जल संचयन को अपनाना, रिसाव वाले नलों की मरम्मत कराना, पेड़ों का संरक्षण और जल स्रोतों को स्वच्छ रखना ऐसे कदम हैं, जिनका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। कृषि क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देकर भी पानी की बड़ी मात्रा बचाई जा सकती है।विद्यालयों और महाविद्यालयों में जल संरक्षण को व्यवहारिक शिक्षा का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी बचपन से ही इस विषय के प्रति संवेदनशील बने। मीडिया, सामाजिक संगठनों और स्थानीय प्रशासन को भी जन-जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को पानी के महत्व और उसके संरक्षण के प्रति प्रेरित करना चाहिए। जल संकट केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास का भी प्रश्न है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े दो संशोधन विधेयक किए पारित

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े दो संशोधन विधेयक पारित किए, जिसमें 66 समुदायों को सूची में शामिल किया गया। इसमें 54 हिंदू और 12 मुस्लिम समुदाय हैं। आरक्षण व्यवस्था को कानूनी रूप से मजबूत और पारदर्शी बनाने का दावा किया गया है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सोमवार को अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण व्यवस्था से जुड़े दो महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों को पारित कर राज्य की आरक्षण नीति में बड़ा बदलाव कर दिया। इन संशोधनों के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी से बाहर की 66 समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान किया गया है। इनमें 54 हिंदू और 12 मुस्लिम समुदाय शामिल हैं। राज्य सरकार का दावा है कि यह कदम आरक्षण व्यवस्था को कानूनी रूप से मजबूत और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। विधानसभा में पारित किए गए दोनों विधेयकों में पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग को फिर से अधिक अधिकार दिए गए हैं। साथ ही तृणमूल कांग्रेस सरकार के समय तैयार की गई अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों की सूची को कानूनी मान्यता देने वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री गौरिशंकर घोष ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक 2026 तथा पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। बहस और मत विभाजन के बाद दोनों विधेयक पारित हो गए। इन संशोधनों के माध्यम से वर्ष 2012 में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए बदलावों को वापस लेने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि पिछली सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ मुस्लिम समुदायों को असंतुलित तरीके से दिया, जबकि कई सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हिंदू समुदायों की अनदेखी की गई। नई व्यवस्था में मुस्लिम समुदायों की संख्या को काफी घटाया गया है। पहले की तृणमूल सरकार द्वारा तय ढांचे में 65 मुस्लिम उपसमूह शामिल थे, जबकि अब केवल 12 मुस्लिम समुदाय ही सूची में रखे गए हैं। इसी तरह हिंदू उपसमूहों की संख्या में भी बदलाव किया गया है। दरअसल, तृणमूल सरकार ने पहले अन्य पिछड़ा वर्ग सूची को बढ़ाकर 113 उपसमूह कर दिया था, जिनमें 77 मुस्लिम और 36 हिंदू समुदाय शामिल थे। बाद में इसे बढ़ाकर 140 उपसमूह कर दिया गया, जिनमें 77 मुस्लिम और 63 हिंदू समुदाय शामिल थे। इस व्यवस्था को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। वर्ष 2025 में उच्च न्यायालय ने इस सूची को रद्द कर दिया और कहा कि समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने की प्रक्रिया कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं थी। अदालत ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार ने आयोग की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। बाद में उच्चतम न्यायालय ने कुछ मामलों में रोक हटाई, लेकिन अब नई सरकार ने व्यवस्था को फिर से पुराने 66 समुदायों वाले ढांचे पर ला दिया है। हम आपको याद दिला दें कि मई 2024 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 के बाद जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया था। अदालत का मानना था कि समुदायों को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया में गंभीर कानूनी कमियां थीं। इसके बाद इस साल मई में सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अधिसूचना जारी कर अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को पहले के 17 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया था। यह आरक्षण राज्य की 66 अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों तक सीमित कर दिया गया। नए संशोधनों के अनुसार राज्य सरकार पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करके अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का प्रतिशत तय करेगी और समय समय पर उसमें बदलाव भी कर सकेगी। हालांकि कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। सरकार को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह आयोग की सिफारिशों के आधार पर पिछड़ेपन की मात्रा के अनुसार समुदायों को अलग-अलग श्रेणियों में बांट सके।

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को रोके जाने पर विपक्ष का हमला

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा और दान राशि में कथित अनियमितताओं के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। इस प्रकरण में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से कई घंटों तक पूछताछ होने के बाद विपक्ष लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर है। इसी बीच कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल को राम मंदिर परिसर जाने से रोके जाने पर नया विवाद खड़ा हो गया।कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे श्रद्धालु के रूप में दर्शन करने और मामले की वास्तविक स्थिति जानने पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार इस पूरे मामले में पारदर्शिता से बच रही है। कांग्रेस ने मांग की कि जांच निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो।वहीं समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को रोके जाने का विरोध किया। पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि यदि भाजपा यह कहती रही है कि विपक्ष राम मंदिर नहीं जाता, तो दर्शन के लिए पहुंचे नेताओं को रोकने का कोई औचित्य नहीं है। विपक्षी दलों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए।भाजपा ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से कुछ समय के लिए प्रवेश पर नियंत्रण रखा गया था और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। भाजपा ने दोहराया कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही हैं तथा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। आगामी दिनों में जांच की प्रगति और विपक्ष की रणनीति इस मुद्दे को और अधिक राजनीतिक रूप दे सकती है।

मिशन पंजाब पर कांग्रेस-भाजपा की नजर संगठन मजबूत करने की कवायद तेज

पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस और भाजपा दोनों ने राज्य में अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। दोनों दल संगठन को मजबूत करने, नए चेहरों को आगे लाने और कार्यकर्ताओं के बीच सक्रियता बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।कांग्रेस राज्य में पिछले कुछ समय से कमजोर पड़े संगठन को दोबारा मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। पार्टी नेतृत्व जिला और ब्लॉक स्तर पर बैठकों का सिलसिला तेज कर चुका है। साथ ही ऐसे नेताओं को फिर से सक्रिय भूमिका देने पर विचार किया जा रहा है जो लंबे समय से सार्वजनिक राजनीति से दूर रहे हैं।इसी क्रम में पूर्व क्रिकेटर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की सक्रिय राजनीति में वापसी की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संगठन के भीतर इस विषय पर लगातार चर्चा जारी है।दूसरी ओर भाजपा भी पंजाब में अपने जनाधार का विस्तार करने के लिए लगातार अभियान चला रही है। पार्टी किसान, युवा, महिला और शहरी मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है। केंद्रीय नेतृत्व भी राज्य के नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर चुनावी रणनीति तैयार कर रहा है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंजाब में इस बार मुकाबला काफी रोचक हो सकता है। कांग्रेस जहां अपने पुराने जनाधार को वापस पाने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों के सहारे अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी है। आने वाले महीनों में दोनों दलों की रणनीति राज्य की राजनीति की दिशा तय कर सकती है।

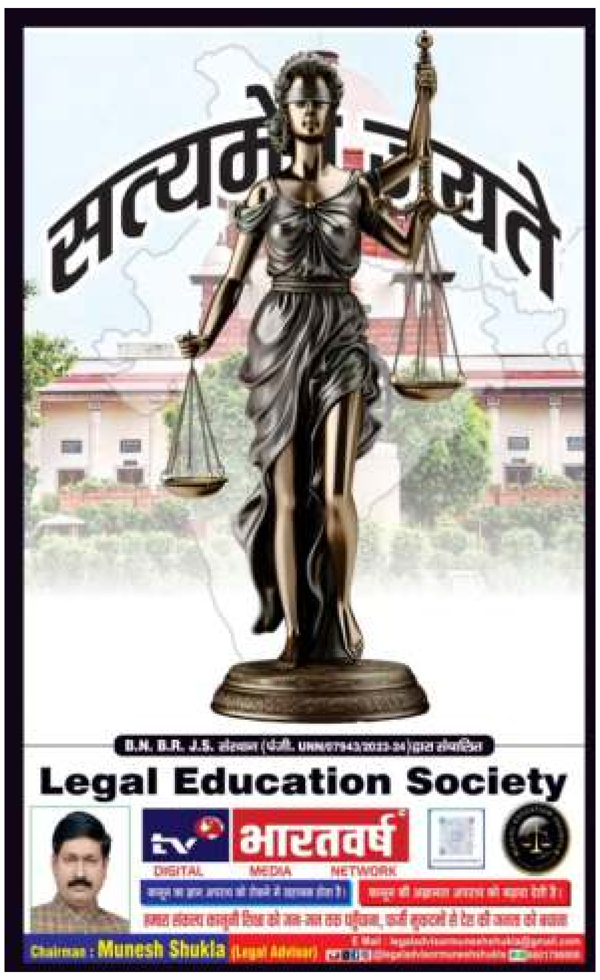

देश के प्रमुख IIT में 40% प्रोफेसरों के पद खाली शिक्षा की गुणवत्ता पर उठे सवाल

देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में शिक्षकों की भारी कमी एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। ताजा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश के 23 IIT में स्वीकृत फैकल्टी पदों में से लगभग 40 प्रतिशत पद अभी भी रिक्त हैं। सबसे अधिक प्रभाव पुराने और प्रमुख संस्थानों, जैसे IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास और IIT रुड़की में देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक शिक्षकों के पद खाली रहने से न केवल छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि शोध कार्य, नवाचार और संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है।शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में IIT में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ी है, लेकिन उसी अनुपात में स्थायी शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं हो सकीं। कई विभागों में एक ही प्रोफेसर को कई विषय पढ़ाने पड़ रहे हैं, जबकि कुछ विभाग अतिथि शिक्षकों और संविदा फैकल्टी के सहारे चल रहे हैं। इससे छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन, प्रयोगशाला कार्य और शोध परियोजनाओं में अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। पीएचडी और एमटेक के विद्यार्थियों को शोध पर्यवेक्षक मिलने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि फैकल्टी की कमी का असर उद्योग और अकादमिक संस्थानों के बीच होने वाले अनुसंधान सहयोग पर भी पड़ रहा है। कई महत्वपूर्ण रिसर्च प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जबकि नई तकनीकों और स्टार्टअप से जुड़े नवाचार कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त शोध और छात्र-शिक्षक आदान-प्रदान कार्यक्रमों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है।केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए जा रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार देश और विदेश में कार्यरत योग्य भारतीय वैज्ञानिकों और शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए बेहतर वेतन, आधुनिक अनुसंधान सुविधाएं, स्टार्टअप समर्थन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। कई IIT ने ऑनलाइन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी फैकल्टी भर्ती प्रक्रिया शुरू की है ताकि योग्य उम्मीदवारों को जोड़ा जा सके।शिक्षा क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि यदि समय रहते रिक्त पद नहीं भरे गए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत अनुसंधान, नवाचार और विश्वस्तरीय तकनीकी शिक्षा के लक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं। उद्योग जगत ने भी सरकार से मांग की है कि IIT जैसे प्रमुख संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि यही संस्थान देश के भविष्य के वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ तैयार करते हैं।विशेषज्ञों का मानना है कि केवल नए संस्थान खोलना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनमें अनुभवी और योग्य शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है। आने वाले समय में केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय और IIT प्रशासन द्वारा उठाए जाने वाले कदम यह तय करेंगे कि देश के शीर्ष तकनीकी संस्थान अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा और शैक्षणिक उत्कृष्टता को किस तरह बनाए रखते हैं।

बिहार के 211 डिग्री कॉलेजों में नहीं शुरू हो सकी पढ़ाई, अधूरी तैयारियां बनीं वजह

बिहार में उच्च शिक्षा व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। राज्य के 211 नए डिग्री कॉलेजों में अधूरी तैयारियों के कारण शैक्षणिक सत्र समय पर शुरू नहीं हो सका। इन कॉलेजों में भवन, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, फर्नीचर और शिक्षकों की नियुक्ति जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं पूरी नहीं होने के कारण छात्रों को इंतजार करना पड़ रहा है।राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के उद्देश्य से इन कॉलेजों की स्थापना की थी, लेकिन आवश्यक संसाधनों की कमी के कारण अधिकांश संस्थान अभी पूरी तरह संचालन के लिए तैयार नहीं हैं। इससे हजारों विद्यार्थियों के प्रवेश और नियमित पढ़ाई पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।शिक्षा विभाग का कहना है कि अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। भवन निर्माण, उपकरणों की उपलब्धता और शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है ताकि आगामी सत्र में सभी कॉलेज पूरी क्षमता के साथ संचालित हो सकें।शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि केवल नए कॉलेज खोलना पर्याप्त नहीं है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए आधारभूत ढांचा, योग्य शिक्षक और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं भी समय पर उपलब्ध कराना जरूरी है। छात्रों और अभिभावकों को उम्मीद है कि सरकार जल्द आवश्यक तैयारियां पूरी कर इन कॉलेजों में नियमित शिक्षण कार्य शुरू कराएगी।

जर्मनी का टूटा वर्ल्ड कप का सपना पैराग्वे ने पेनल्टी शूटआउट में किया बड़ा उलटफेर

वैभव के डेब्यू को लेकर श्रेयस अय्यर ने कहा- टीम के खिलाड़ियों का समर्थन जरूरी

आयरलैंड के खिलाफ हाल ही में हुई दो मैचों की टी-20 सीरीज में 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका नहीं मिला। इस बात से क्रिकेट फैंस काफी नाराज हैं। अब भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेलने जा रही है। ऐसे में हर कोई यही सोच रहा है कि क्या वैभव को इस सीरीज में खेलने का मौका मिलेगा? इंग्लैंड के खिलाफ चेस्टर-ली-स्ट्रीट में होने वाले पहले मैच से पहले, कप्तान श्रेयस अय्यर से भी वैभव के डेब्यू को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर अय्यर ने सीधे-सीधे जवाब न देकर सस्पेंस बनाए रखा है। जब कप्तान श्रेयस अय्यर से हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या वैभव सूर्यवंशी इस मैच में अपना डेब्यू करेंगे, तो उन्होंने टीम की प्लानिंग को सीक्रेट रखा। अय्यर ने कहा कि हमारे हाथ बंधे हैं और यह टीम का अंदरूनी मामला है। हम सबको अपनी टीम के कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि इससे विरोधी टीम को हमारी रणनीति का पता चल जाएगा। वैभव बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और जब भी उन्हें मौका मिलेगा, वह बेहतरीन खेल दिखाएंगे। श्रेयस अय्यर ने इस दौरान ये भी कहा कि टीम के बाकी खिलाड़ियों का साथ देना बहुत जरूरी है। उन्होंने समझाया कि सिर्फ एक खिलाड़ी ने ही अच्छा नहीं खेला है, बल्कि दूसरे खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों के मन से डर दूर करने और उनमें भरोसा जगाने के लिए उन्हें टीम में लगातार मौके देना जरूरी है। वे खिलाड़ी टीम की जान हैं और वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में भी शामिल रहे हैं, इसलिए इस मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहना बहुत अहम है।

क्या है 'रिटर्न टू प्ले मॉडल' ऑस्ट्रेलिया की डॉक्टर करेगी अगुआई

महिला क्रिकेटरों के लिए आईसीसी ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि मां बनने के बाद भी खिलाड़ी आसानी से क्रिकेट में वापसी कर सकें और उनका करियर प्रभावित न हो। ICC की इस नई 'रिटर्न टू प्ले पोस्ट-प्रेग्नेंसी गाइडलाइन' में सदस्य देशों के क्रिकेट बोर्डों को कई सुझाव दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि हर खिलाड़ी के लिए एक विशेष केस मैनेजर नियुक्त (अपॉइंट) किया जाए। यह डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है, जो प्रेग्नेंसी से लेकर क्रिकेट में वापसी तक खिलाड़ी की मदद करेगा। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि खिलाड़ियों को लचीला ट्रेनिंग माहौल, बच्चों की देखभाल की सुविधा, यात्रा में सहायता और मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसका फायदा उन खिलाड़ियों को मिलेगा जो अपने खेल करियर के दौरान परिवार शुरू करना चाहती हैं। आईसीसी ने वापसी के लिए छह स्टेज का मॉडल भी तैयार किया है। इसमें रेडी, रिव्यू, रिस्टोर, रिकंडीशन, रिटर्न और रिफाइन जैसे चरण शामिल हैं। इन चरणों के जरिए खिलाड़ी धीरे-धीरे फिटनेस हासिल कर दोबारा क्रिकेट जैसे मैदानी खेल में लौट सकेगी। नई गाइडलाइन के अनुसार किसी खिलाड़ी पर प्रेग्नेंसी की घोषणा करने का दबाव नहीं डाला जाएगा। यह पूरी तरह खिलाड़ी का निजी फैसला होगा। साथ ही बोर्ड खिलाड़ियों के लिए अनिवार्य प्रेग्नेंसी टेस्ट भी नहीं कर सकेंगे। आईसीसी ने यह भी साफ किया है कि प्रेग्नेंसी के दौरान ट्रेनिंग और खेलने का फैसला हर खिलाड़ी की स्वास्थ्य स्थिति को देखकर किया जाएगा। इसके लिए खिलाड़ी, डॉक्टर और मेडिकल टीम मिलकर निर्णय लेंगे। इस पहल की अगुआई ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम की डॉक्टर फिलिपा इंगे ने की है। उनका कहना है कि बच्चा होना किसी महिला क्रिकेटर के करियर का अंत नहीं होना चाहिए।

क्वार्टर फाइनल में धीमी पारी भारतीय टीम पर भारी पड़ी

वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 से भारतीय टीम का सफर समाप्त हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए करो या मरो मुकाबले में टीम इंडिया को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। लॉर्ड्स में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 170 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 171 रन के लक्ष्य को 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस मुकाबले में टीम इंडिया की चार खिलाड़ियों की गलतियां उस पर भारी पड़ गईं, जिसकी वजह से एक बार फिर वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया। जब भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने टीम को काफी धीमी शुरूआत दिलाई। स्मृति मंधाना ने 37 गेंदों पर सिर्फ 38 रन बनाए। टी20 वर्ल्डकप के इस वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में उनकी यह धीमी पारी भारतीय टीम पर भारी पड़ी, जिसकी वजह से बाकी बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता गया। शेफाली वर्मा भी 26 गेंदों पर सिर्फ 34 रन ही बना सकीं, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स ने 28 गेंदों पर 34 रन बनाए। केवल कप्तान हरमनप्रीत कौर ही ऐसी बल्लेबाज रहीं, जिन्होंने 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उनकी 27 गेंदों में ताबड़तोड़ 56 रन की पारी की बदौलत भारतीय टीम 20 ओवर में 170 रन तक पहुंचने में सफल रही। 171 रन के लक्ष्य का बचाव करने उतरी भारतीय टीम की गेंदबाजी भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। टूर्नामेंट की सबसे प्रभावशाली गेंदबाजों में शामिल दीप्ति शर्मा सिर्फ एक विकेट ही हासिल कर सकीं।

93 की उम्र में भी थिएटर में काम कर रहीं महिला

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक 93 साल की महिला मूवी थियेटर में काम कर अपना गुजारा कर रही हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही फिल्म खत्म होती है, दर्शक हॉल से बाहर निकलते दिखते हैं. उसी वक्त महिला अपना काम शुरू कर देती हैं. वह वहां बिखरे कचरे को धीरे-धीरे समेटती है. वह खाली बोतलें और खाने के पैकेट इकट्ठा करती हैं, ताकि अगला शो समय पर शुरू हो सके.

मिलावट का नया तरीका या कलाकार की जादुई कला?

समोसे पर ब्रश से रंग का अनोखा खेल

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में एक शख्स समोसे जैसी दिखने वाली चीजों पर ब्रश से रंग लगाता नजर आता है. इसके बाद कुछ लोगों ने मिलावट का दावा किया.

एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को कन्फ्यूज कर दिया है.

पहली नजर में ऐसा लगता है कि एक शख्स समोसों पर ब्रश से रंग लगा रहा है. वीडियो सामने आते ही कई लोगों ने इसे खाने में मिलावट का मामला बता दिया, जबकि एक दावा ये भी है कि ये खाने वाले समोसे नहीं, बल्कि सजावट के लिए बनाए गए नकली समोसे हैं. फिलहाल वीडियो को लेकर जमकर बहस छिड़ी हुई है.

वायरल क्लिप में एक व्यक्ति जमीन पर बैठा दिखाई देता है. उसके आसपास समोसे जैसी चीजें रखी हैं. कुछ का रंग हल्का है, जबकि कुछ पहले से सुनहरे रंग की दिखाई देती हैं. वह ब्रश की मदद से इन पर रंग लगाता नजर आता है. पास में रंग से भरे छोटे-छोटे डिब्बे भी रखे हुए हैं. ये नजारा लोगों को उलझन में डाल रहा है, क्योंकि यह किसी कुकिंग प्रोसेस से ज्यादा पेंटिंग जैसा दिखाई देता है.यह वीडियो X पर शेयर किये गया है. जिसका कैप्शन है- मुझे लगा था समोसे शुद्ध होते हैं, लेकिन यहां भी मिलावट हो रही है. इसके बाद वीडियो तेजी से वायरल हो गया और कई लोगों ने खाने की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए. वीडियो पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. एक यूजर ने लिखा कि समोसे को रंगने की क्या जरूरत है.

सच्चाई अब भी साफ नहीं

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वीडियो में दिख रही वस्तुएं वास्तव में खाने वाले समोसे हैं या सजावट के लिए तैयार किए गए खिलौने . इस वीडियो या उससे जुड़े दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है.फिलहाल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग अपनी-अपनी समझ के अनुसार इसकी अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने AI तस्वीर शेयर की

'एटलस' बने ट्रंप, फिर छिड़ी बहस

ट्रंप ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक AI-जनरेटेड तस्वीर शेयर की. तस्वीर में वह ग्रीक पौराणिक पात्र 'एटलस' की तरह पूरी धरती को अपने कंधों पर उठाए नजर आ रहे हैं. तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपनी AI तस्वीर को लेकर चर्चा में हैं. इस बार उन्होंने ट्रुथ सोशल पर ऐसी तस्वीर शेयर की, जिसमें वह ग्रीक पौराणिक पात्र एटलस (Atlas) की तरह एक घुटने पर बैठे हैं और पूरी धरती को अपने कंधों पर उठाए हुए दिखाई दे रहे हैं. उनके शरीर पर अमेरिकी झंडा भी लिपटा हुआ है. ट्रंप ने तस्वीर के साथ कोई कैप्शन नहीं लिखा. ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग इसके अलग-अलग मायने निकाल रहे हैं. ग्रीक पौराणिक कथाओं के मुताबिक, एटलस एक शक्तिशाली टाइटन था. देवताओं के खिलाफ युद्ध हारने के बाद उसे सजा मिली कि वह हमेशा के लिए आसमान या दुनिया का भार अपने कंधों पर उठाए रखेगा. इसलिए आज भी किसी बड़े बोझ या भारी जिम्मेदारी के प्रतीक के रूप में एटलस का जिक्र किया जाता है. ट्रंप ने इस तस्वीर का मतलब नहीं बताया है. हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के आधार पर इसके कई संभावित अर्थ निकाले जा रहे हैं. तस्वीर में ट्रंप खुद को ऐसे नेता के रूप में पेश करते दिखाई देते हैं, जो पूरी दुनिया का भार संभाल सकता है. इसे उनके समर्थक मजबूत नेतृत्व के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं. एटलस सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि भारी जिम्मेदारी का भी प्रतीक है. कई लोगों का मानना है कि ट्रंप इस तस्वीर के जरिए यह संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया के बड़े संकटों से निपटने की जिम्मेदारी वह उठाने में सक्षम हैं.

पहले भी शेयर कर चुके हैं ऐसी तस्वीरें

यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने AI-जनरेटेड या डिजिटल रूप से तैयार तस्वीर शेयर की हो. इससे पहले भी वह कई ऐसी तस्वीरें साझा कर चुके हैं, जिनमें खुद को असाधारण या ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के साथ जोड़ा गया था. फिलहाल ट्रंप या व्हाइट हाउस की ओर से यह नहीं बताया गया है कि एटलस वाली AI तस्वीर शेयर करने के पीछे उनकी आधिकारिक मंशा क्या थी.

'सॉरी दीदी' बोलकर लड़कियों को मारता था टक्कर, अब अरेस्ट

सोशल मीडिया पर व्यूज और फॉलोअर्स की होड़ अब खतरनाक होती जा रही है. वायरल होने और ज्यादा कमाई के लिए कुछ लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जो सीधे कानून की सीमा लांघ रही हैं. दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है, जिस पर महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को सड़क पर जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान 32 वर्षीय गुरमन सिंह के रूप में हुई है.

फैंस के लिए सरप्राइज से कम नहीं 'रामायण' की एक्सक्लूसिव झलक

रणबीर कपूर और यश ने दिखाई 'रामायण' फिल्म की झलक

150 से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खास इवेंट, 15 मिनट के प्रेजेंटेशन ने बढ़ाई उत्सुकता

मुंबई, शुक्रवार

बॉलीवुड की सबसे चर्चित और बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है। अब फिल्म के मेकर्स ने इस एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है। हाल ही में फिल्म के लीड स्टार्स रणबीर कपूर और यश ने 150 से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक खास इवेंट आयोजित किया, जहां उन्हें फिल्म की एक्सक्लूसिव झलक

इस इवेंट में मौजूद लोगों को करीब 15 मिनट का खास प्रेजेंटेशन दिखाया गया। इसमें फिल्म के कई ऐसे विजुअल्स शामिल थे, जिन्हें अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया था। इसके अलावा मेकिंग, बड़े-बड़े सेट्स और पर्दे के पीछे की मेहनत की भी झलक दिखाई गई।

15 मिनट की खास झलक ने बढ़ाया रोमांच

कौन निभा रहा है कौन-सा किरदार?

- **रणबीर कपूर** – भगवान राम
- **साई पल्लवी** – माता सीता
- **रवि दुबे** – लक्ष्मण
- **यश** – रावण
- **सनी देओल** – भगवान हनुमान

रणबीर कपूर और यश को साथ देखकर खुश हुए फैंस

इवेंट की सबसे बड़ी हाइलाइट रणबीर कपूर और यश की मौजूदगी रही। दोनों स्टार्स ने कंटेंट क्रिएटर्स से मुलाकात की और तस्वीरें भी खिंचवाईं। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये तस्वीरें सामने आईं, फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई, खासकर इसलिए क्योंकि फिल्म में दोनों एक-दूसरे के आमने-सामने नजर आने वाले हैं।

दो पार्ट में रिलीज होगी फिल्म

पहला पार्ट
दिवाली 2026 पर दुनियाभर के IMAX सिनेमाघरों में रिलीज होगा।

दूसरा पार्ट
दिवाली 2027 में दर्शकों के सामने आएगा।

भव्य निर्माण, दमदार टीम

फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं। इमर्माण नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियोज, ऑस्कर विजेता VFX कंपनी DNEG और यश की मॉन्स्टर माईड क्रिएशंस मिलकर कर रहे हैं।

> "यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था की सबसे बड़ी सिनेमाई प्रस्तुति हैं।
> – मेकर्स

योगी सरकार का बड़ा फैसला,

1 जुलाई से ग्राम सचिवालयों में नियमित बैठेंगे लेखपाल

1 जुलाई से उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम सचिवालयों में रोस्टर के अनुसार लेखपाल नियमित बैठेंगे। इससे ग्रामीणों को आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र, खतौनी की नकल सहित अन्य राजस्व सेवाएं गांव में ही मिलेंगी और तहसील के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।

उत्तर प्रदेशकी योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन और जनसेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथकी मंशा के अनुरूप अब प्रदेश के सभी जनपदों में लेखपालों की ग्राम सचिवालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत एक जुलाई से प्रत्येक जनपद में रोस्टर के आधार पर लेखपाल ग्राम सचिवालयों में बैठेंगे और ग्रामीणों की राजस्व संबंधी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। सरकार के इस फैसले से अब ग्रामीणों को आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र, खतौनी की नकल और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए बार-बार तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्व परिषद की ओर से इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अधिकारियों को लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और ग्राम सचिवालयों को जनसेवा केंद्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उनकी समस्याओं का समाधान गांव में ही हो, इसके लिए राज्य सरकार लगातार नई पहल कर रही है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अब ग्राम सचिवालयों को और अधिक सशक्त बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि गांव के लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए समय और धन दोनों की बचत हो तथा उन्हें अपने ही गांव में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। लेखपालों की नियमित उपस्थिति इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य ग्राम सचिवालयों को पूरी तरह 'वन स्टॉप सर्विस सेंटर' के रूप में विकसित करना है। यानी ग्रामीणों को अलग-अलग विभागों के कार्यों के लिए अलग-अलग कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि एक ही स्थान पर अधिकांश सरकारी सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। पंचायतीराज विभाग पहले से ही ग्राम सचिवालयों के माध्यम से कई विभागों की सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। पंचायत सहायकों के माध्यम से विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। अब लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होने से राजस्व विभाग से जुड़े कार्यों को और अधिक गति मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक मांग आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, हैसियत प्रमाणपत्र और खतौनी की नकल जैसी सेवाओं की रहती है। इन सभी सेवाओं के समयबद्ध निस्तारण में लेखपाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब तक इन कार्यों के लिए ग्रामीणों को कई बार तहसील जाना पड़ता था। कई बार एक छोटे से काम के लिए उन्हें कई दिन तक इंतजार करना पड़ता था। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों खर्च होता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन सेवाओं के लिए ग्रामीण सीधे ग्राम सचिवालय पहुंच सकेंगे और उन्हें अपने गांव में ही आवश्यक सहायता उपलब्ध हो जाएगी।

लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज, रिमझिम बारिश से गर्मी से राहत

लखनऊ के सरोजनीनगर इलाके में सुबह 10:45 रिमझिम बारिश होने लगी। गोमतीनगर में बूंदाबूंदी हुई। शहर के अन्य इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। हवा भी चल रही है। आज बादलों की वजह से धूप नहीं दिखी। मौसम विभाग ने दोपहर में बादलों की गरज-चमक के साथ बारिश की प्रबल संभावना जताई है। हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रहेगा। वहीं, आज से लू का असर खत्म हो जाएगा, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। सोमवार को अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री रहा। यह सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक रहा। अधिकतम आर्द्रता 75 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 49 फीसदी रही।लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया- मानसून ने तराई बेल्ट के रास्ते यूपी में एंट्री ली है। इनमें सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया सहित अन्य जिले शामिल हैं। इसने दोपहर तक में अयोध्या, आजमगढ़ सहित 20 जिलों को कवर कर लिया है। इसका असर राजधानी लखनऊ के साथ आसपास के जिलों में भी देखने को मिल रहा।

निजी प्रैक्टिस के आरोपों में घिरे KGMU प्रोफेसर, आज जांच समिति के सामने रखेंगे पक्ष

लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के फिजियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. संदीप भट्टाचार्य पर निजी प्रैक्टिस करने के गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायत उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल और राजभवन तक पहुंचने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कुलसचिव ने आरोपों की पड़ताल के लिए पांच सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति की बैठक 30 जून को कुलपति कार्यालय में होगी, जिसमें संबंधित प्रोफेसर को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। उनसे आरोपों के संबंध में आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य भी प्रस्तुत करने को कहा गया है। शिकायतकर्ता आईआईएम रोड निवासी फतेह बहादुर सिंह ने आरोप लगाया है कि संबंधित प्रोफेसर KGMU एक्ट और संस्थान के नियमों के विपरीत निजी प्रैक्टिस सहित अन्य गतिविधियों में शामिल हैं। मामले की शिकायत उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल और राजभवन में भी की गई थी। राजभवन से पत्राचार और मेडिकल काउंसिल के संज्ञान के बाद KGMU प्रशासन सक्रिय हुआ। जांच समिति शिकायत, उपलब्ध दस्तावेजों और प्रोफेसर के जवाब की समीक्षा करेगी। समिति यह भी जांचेगी कि संबंधित गतिविधियां विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप थीं या नहीं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।कुलसचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जांच समिति की अध्यक्षता कुलपति के प्रतिनिधि करेंगे। समिति में चीफ प्रॉक्टर के सचिव, डीन एकेडमिक्स, डीन पैरामेडिकल और लीगल सेल के फैकल्टी इंचार्ज को सदस्य बनाया गया है। समिति सभी तथ्यों, दस्तावेजों और संबंधित पक्षों के बयानों के आधार पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।कुलसचिव द्वारा गठित पांच सदस्यीय जांच समिति मंगलवार को बैठक कर शिकायत, उपलब्ध दस्तावेजों और संबंधित प्रोफेसर के जवाब की समीक्षा करेगी। बैठक दोपहर तीन बजे कुलपति कार्यालय में होगी। नोटिस के अनुसार, आरोपित प्रोफेसर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के साथ ही आरोपों से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

अलीगंज अग्निकांड: फर्जी NOC के मामले में भवन मालिक पर नई FIR

लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में एक और FIR दर्ज हुई है। अवैध व्यावसायिक भवन में 22 जून को हुए अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई थी। अब इस अग्निकांड की जांच संबंधित सभी विभाग कर रहे हैं। इस अग्निकांड में विद्युत सुरक्षा विभाग ने आंतरिक जांच की, जिसमें पता चला कि भवन मालिक वीरेंद्र शुक्ला ने जो NOC जमा किया था, वो फर्जी था। विभाग की तरफ से बताया कि नियम-कानून को दरकिनार करके अवैध व्यावसायिक भवन के मालिक वीरेंद्र शुक्ला ने विद्युत सुरक्षा की फर्जी NOC हासिल किया था। जांच पूरी होने के बाद विभाग के सहायक निदेशक ने भवन स्वामी वीरेंद्र शुक्ला के खिलाफ अलीगंज थाने में सोमवार शाम नई FIR दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विद्युत सुरक्षा निदेशालय में तैनात सहायक निदेशक आलोक शुक्ला के मुताबिक, 22 जून को सेक्टर-डी के एमएस-102 भवन में हुए अग्निकांड की जांच के दौरान भवन की विद्युत सुरक्षा NOC का सत्यापन किया गया। जांच में पाया गया कि भवन स्वामी वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला ने जो NOC दिखाया, वह विभागीय अभिलेखों से मेल नहीं खाता। NOC पर अंकित पत्रांक और डिस्पैच संख्या विभाग के रिकॉर्ड में किसी अन्य विषय से संबंधित हैं। इसके अलावा, तत्कालीन सहायक निदेशक के हस्ताक्षर, दस्तावेज का फॉन्ट, लिखावट और पेपर डिजाइन भी विभाग के मूल रिकॉर्ड से अलग पाए गए।

लखनऊ में बहू की बेरहमी से पिटाई, सास और मौसी पर मारपीट का आरोप

पारा थाना क्षेत्र का एक वीडियो सामने आया है। इसमें 2 अधेड़ उम्र की महिलाएं एक एक महिला को डंडे और बेल्ट से पीटती दिख रही हैं। दोनों ने उसके बाल भी नोचे। इस मामले में पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत दे दी है। पुलिस ने बताया है कि सास ने अपनी बहन और छोटे बेटे को बुलाकर बहू को पीटा है। मामले की जांच की जा रही है। घायल महिला की मेडिकल जांच कराई जा रही है। मामला बुद्धेश्वर के आदर्श विहार कॉलोनी का है। पीड़िता सोनी कश्यप ने थाने में दी शिकायत में बताया है- मेरी सास शारदा देवी ने 29 जून को सुबह करीब 9:30 बजे मुझे गाली देनी शुरू कर दी। जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने देवर शिवम को बुला लिया। दोनों ने मुझे लाठी-डंडे से पीटा। मारपीट के बाद देवर घर से भाग गया।कुछ देर बाद सास वहां से गईं और अपनी बहन कमलेश को बुला लाईं। फिर उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। मेरे बाल नोचे। मुझे बेल्ट से पीटा। घर से लेकर दरवाजे के बाहर तक घसीट-घसीटकर मारा। इस दौरान मोहल्ले के लोग तमाशा देखते रहे। इस मारपीट से मेरे सिर में गंभीर चोट आई और काफी खून बह गया। कई बाहरी और अंदरूनी चोटें आई हैं। अस्पताल जाकर इलाज कराना पड़ा है। मारपीट के दौरान मेरे कान से करीब तीन ग्राम वजनी सोने के गहने छीन लिए गए।

अंबेडकर अस्थि कलश विवाद पर गरमाई सियासत, RPI ने दी महाआंदोलन की चेतावनी

लखनऊ में मंगलवार को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) ने भीमराव अंबेडकर के अस्थि कलश को विस्थापित करने के विरोध में प्रदर्शन किया। हजरतगंज चौराहे से विधानभवन के सामने बाबासाहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के अस्थि कलश स्थल तक विरोध मार्च निकालने की कोशिश की। भारी पुलिस फोर्स ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा- किसी भी स्थिति में अस्थि कलश विस्थापित नहीं होने देंगे। पूरे 75 जनपदों में हमारे पार्टी के लोग ज्ञापन देखकर इसका विरोध करेंगे। इसके बावजूद भी सरकार इससे छेड़छाड़ करती है तो 9 अगस्त को लखनऊ में महाआंदोलन होगा। पार्टी किसी भी हाल में देश के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। RPI प्रदेश अध्यक्ष पवन भाई गुप्ता ने कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि देश के संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतीक हैं। ऐसे में उनसे जुड़े किसी भी स्मारक या धरोहर के साथ लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अस्थि कलश हमारे लिए आस्था का विषय है और हम हम अपनी आस्था से खिलवाड़ नहीं होने देंगे।पवन भाई गुप्ता ने कहा कि हम लोग अटल चौक पर स्थित बाबा साहब की प्रतिमा से बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की कलश स्थल तक पैदल यात्रा निकालने जा रहे थे। मगर भारी पुलिस फोर्स लगाकर हमें रोक लिया गया। 1991 में बाबा साहब का अस्थि कलश विधानभवन के बगल में स्थापित किया गया था। उसके बाद राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया था।

बूचड़खानों की जांच की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन, प्रशासन से कार्रवाई की अपील

उन्नाव में भारतीय किसान यूनियन (सावित्री) ने जिले में संचालित कुछ बूचड़खानों के खिलाफ कथित अनियमितताओं और पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मंगलवार को प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह को सौंपा। ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच कराने, पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने और दोषी पाए जाने पर संबंधित इकाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि जिले में संचालित कुछ बूचड़खाने निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से इंडाग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और जे.एस. इंटरनेशनल फूड्स का उल्लेख करते हुए कहा कि इन इकाइयों में नियमों के विपरीत गतिविधियां संचालित किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं। संगठन का कहना है कि यदि इन आरोपों की समय रहते जांच नहीं की गई तो इसका असर पर्यावरण के साथ-साथ स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। भारतीय किसान यूनियन (सावित्री) के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि संबंधित बूचड़खानों से निकलने वाले अपशिष्ट और दूषित पानी का उचित निस्तारण नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि दूषित पानी आसपास के क्षेत्रों में छोड़ा जा रहा है, जिससे जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। इससे खेती-किसानी प्रभावित होने के साथ ही स्थानीय निवासियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने आशंका जताई कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो क्षेत्र में जल प्रदूषण बढ़ने के साथ विभिन्न बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। किसान नेताओं ने कहा कि उद्योगों को संचालन की अनुमति शासन द्वारा निर्धारित नियमों और पर्यावरणीय मानकों के आधार पर दी जाती है। ऐसे में इन मानकों का पालन सुनिश्चित कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने मांग की कि संबंधित इकाइयों की विस्तृत जांच कराई जाए और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े सभी नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मंगलवार दोपहर किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह से मुलाकात कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बूचड़खानों के संचालन की जांच, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की प्रभावी निगरानी तथा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की गई। संगठन ने कहा कि पर्यावरण और जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती और प्रशासन को इस दिशा में गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह ने किसान प्रतिनिधियों से ज्ञापन प्राप्त करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि शिकायतों की नियमानुसार जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के माध्यम से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। यदि जांच में किसी भी स्तर पर अनियमितता या पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित इकाइयों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि जनहित, पर्यावरण संरक्षण और कानून के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

उन्नाव में आउटर रिंग रोड के लिए चला बुलडोजर, कड़ेड़ पतारी गांव के मकान ध्वस्त

उन्नाव में कानपुर देहात से उन्नाव तक प्रस्तावित आउटर रिंग रोड के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। इसी क्रम में मंगलवार दोपहर विकासखंड सिकंदरपुर कर्ण के कड़ेड़ पतारी गांव में रिंग रोड की जद में आ रहे मकानों को प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग की टीम और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। यह कार्रवाई कानपुर देहात से उन्नाव तक बनने वाले आउटर रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कड़ेड़ पतारी गांव में चिह्नित मकानों को हटाया गया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बदरका चौकी प्रभारी अपने पुलिस बल के साथ मौके पर तैनात रहे। मौके पर नायब तहसीलदार धीरज त्रिपाठी भी उपस्थित थे। राजस्व विभाग की टीम ने पहले से चिह्नित किए गए निर्माणों की जांच की, जिसके बाद उन्हें बुलडोजर से हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने बताया कि रिंग रोड निर्माण में बाधा बन रहे चिह्नित निर्माणों को नियमानुसार हटाया जा रहा है। आउटर रिंग रोड परियोजना पर लंबे समय से काम चल रहा है। यह सड़क कानपुर देहात से शुरू होकर उन्नाव तक प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य शहरों में बढ़ते यातायात दबाव को कम करना और आवागमन को सुगम बनाना है। इस परियोजना के तहत कई गांवों में भूमि अधिग्रहण और निर्माण हटाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कार्रवाई के दौरान आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए थे। प्रशासन ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिन स्थानों पर निर्माण रिंग रोड की सीमा में आ रहे हैं, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में भी चिह्नित स्थानों पर ऐसी कार्रवाई जारी रहने की संभावना है।

उन्नाव में पोनी रोड चौड़ीकरण को लेकर PWD के नोटिस

उन्नाव शहर में पोनी रोड चौड़ीकरण को लेकर लोक निर्माण विभाग (PWD) ने मंगलवार को भवन स्वामियों के घरों पर नोटिस चस्पा किए। इन नोटिसों के बाद क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया है। सड़क की चौड़ाई बढ़ाने को लेकर भवन स्वामियों में नाराजगी भी देखी जा रही है। लोगों का आरोप है कि पहले तय चौड़ाई से अधिक जमीन लेने की तैयारी की जा रही है। सदर विधायक पंकज गुप्ता के निर्देश पर पोनी रोड के चौड़ीकरण के साथ ही डामर सड़क निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। इसी संबंध में पिछले माह सदर विधायक ने लोक निर्माण विभाग और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने पांच जून से सड़क की नापजोख का काम शुरू कराया था, जिसमें सड़क के दोनों ओर चार-चार मीटर तक निशान लगाए गए थे। लोक निर्माण विभाग की टीम ने सड़क किनारे बने करीब सौ भवनों पर नोटिस चस्पा किए हैं। इन नोटिसों में भवन स्वामियों से कहा गया है कि वे अपने स्थायी और अस्थायी निर्माण को स्वयं हटा लें। ऐसा न करने पर पुलिस बल की मौजूदगी में निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। भवन स्वामियों को किसी भी आपत्ति या अभिलेखीय साक्ष्य के साथ चार जुलाई तक लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड कार्यालय में सहायक अभियंता बीके श्रीवास्तव और एके गुप्ता से संपर्क करने का समय दिया गया है। नोटिस चस्पा होने के बाद क्षेत्रीय लोगों ने विरोध जताया है। भवन स्वामियों का कहना है कि पोनी रोड की चौड़ाई पहले ही आठ मीटर निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसमें एक मीटर और बढ़ाने की बात कही जा रही है। लोगों का सवाल है कि जब पहले से सड़क चौड़ीकरण के लिए जगह निर्धारित थी, तो अतिरिक्त जमीन लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इस मामले पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता एचडी अहरवार ने बताया कि चौड़ीकरण के लिए जहां तक निशान लगाए गए हैं, उतनी ही जमीन ली जाएगी।

उन्नाव में तेज रफ्तार वाहन का कहर, मजदूर की जान गई

उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक अज्ञात वाहन की टक्कर से साइकिल सवार मजदूर की मौत हो गई। मृतक जय प्रकाश पुत्र स्व. अमर लाल, निवासी किशुन खेड़ा, थाना पुरवा मझगवां गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बताया गया कि जय प्रकाश मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। मंगलवार को वह साइकिल से बिहार थाना क्षेत्र के मझगवां गांव में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकला था। इसी दौरान मौकमगंज-मझगवां मार्ग पर एक अज्ञात वाहन ने उसकी साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद जय प्रकाश गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गया। राहगीरों ने तत्काल घटना की जानकारी परिजनों और पुलिस को दी। हालांकि, जब तक उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की जाती, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना स्थल पर पहुंचे परिवार के सदस्य शव देखकर बिलख पड़े।

बांगरमऊ में दूलम सिंह आईटीआई का शुभारंभ

बांगरमऊ में मंगलवार को दूलम सिंह आईटीआई का भव्य उद्घाटन किया गया। इस समारोह में क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद विनय कटियार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस संस्थान का उद्देश्य क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा प्रदान कर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। दोनों अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर संस्थान का विधिवत शुभारंभ किया। यह उद्घाटन समारोह बांगरमऊ में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। इस अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए विधायक श्रीकांत कटियार ने संस्थान प्रबंधन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह संस्थान सरकार की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को कुशल बनाकर 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के प्रबंधक बी.बी. कुशवाहा ने मुख्य अतिथि विधायक श्रीकांत कटियार और विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद विनय कटियार का बुके और शॉल भेंट कर स्वागत किया। दूलम सिंह पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य अर्पित सिंह ने सभी आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया। समारोह में डॉ. विजनेश कटियार और अनुराग सिंह कुशवाहा भी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस पहल को क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक बताया। अंबापारा के ग्राम प्रधान आलोक सिंह कुशवाहा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और इसे ग्रामीण युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर बताया। क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिक विजय द्विवेदी और अजय द्विवेदी भी मौजूद रहे।

उन्नाव में झमाझम बारिश से मिली गर्मी से राहत, मौसम हुआ सुहावना

उन्नाव में भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को मंगलवार सुबह मौसम ने राहत दी। सुबह से आसमान में बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ जिले के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। करीब नौ बजे शुरू हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। आसीवन, सफीपुर, गंजमुरादाबाद, बांगरमऊ, शुक्लागंज और उन्नाव शहर समेत जिले के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को मौसम बदलने के बाद काफी राहत मिली। हालांकि, कुछ स्थानों पर बारिश के कारण जलभराव और कीचड़ की समस्या भी देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को जिले का अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में कमी आने से गर्मी और उमस का असर कम हो गया और मौसम सुहावना हो गया।लगातार गर्मी के कारण खेतों की नमी कम हो रही थी और किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे। मंगलवार की बारिश को किसानों ने खरीफ फसलों के लिए लाभकारी बताया। उनका कहना है कि इससे खेतों में पर्याप्त नमी आएगी और धान की नर्सरी समेत अन्य फसलों की तैयारी में मदद मिलेगी। किसान रामलाल और हरिप्रसाद ने बताया कि लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण सिंचाई पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा था। अब बारिश से खेतों को फायदा मिलेगा और फसलों की बढ़वार बेहतर होने की उम्मीद है।

सपा विधायक कमाल अख्तर ने मुख्य सचेतक पद से दिया इस्तीफा

सपा विधायक कमाल अख्तर ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस कदम से पार्टी में हलचल बढ़ गई है और आंतरिक खींचतान की चर्चा तेज हो गई है।

समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता और मुरादाबाद की कांठ विधानसभा सीट से विधायक कमाल अख्तर ने विधानमंडल के मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस फैसले के बाद पार्टी के भीतर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं और इसे संगठनात्मक स्तर पर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, कमाल अख्तर के इस्तीफे के पीछे पिछले कुछ दिनों से चल रही अंदरूनी खींचतान को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। हाल ही में उनकी पार्टी सांसद रुचि वीरा के साथ अनबन की खबरें सामने आई थीं, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लखनऊ में दोनों पक्षों के साथ बैठक कर पूरे मामले पर चर्चा की थी। बैठक के बाद माना जा रहा था कि विवाद सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब कमाल अख्तर के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा देने की खबर ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। हालांकि, कमाल अख्तर ने अपने इस्तीफे के पीछे की वजह को लेकर अभी तक सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया है। वहीं, समाजवादी पार्टी की ओर से भी इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। कमाल अख्तर का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब पार्टी आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर लगातार संगठनात्मक स्तर पर सक्रिय है। ऐसे में उनके इस कदम को सपा की आंतरिक राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है।रिपोर्ट्स के मुताबिक, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुरादाबाद की कांठ विधानसभा सीट से विधायक कमाल अख्तर का जन्म 24 अक्टूबर 1971 को अमरोहा जिले के उझारी गांव में हुआ। उनके पिता नफीसुद्दीन अहमद और माता महजबीन लंबे समय से स्थानीय राजनीति से जुड़े रहे हैं। शुरुआती शिक्षा के बाद कमाल अख्तर ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र और एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति का रास्ता चुना और समाजवादी पार्टी के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। कमाल अख्तर ऐसे राजनीतिक परिवार से आते हैं, जहां कई पीढ़ियां जनप्रतिनिधि रही हैं। उनके पिता नफीसुद्दीन अहमद लगातार तीन बार उझारी गांव के प्रधान चुने गए और बाद में 1988 से 1993 तक उझारी नगर पंचायत के चेयरमैन रहे। उनकी माता महजबीन भी तीन बार नगर पंचायत अध्यक्ष बनीं। इसके बाद उनकी पत्नी हुमेरा अख्तर ने भी नगर पंचायत की कमान संभाली। यही वजह रही कि कमाल अख्तर को बचपन से ही राजनीतिक माहौल और जनसंपर्क का अनुभव मिला।

उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक, कई जिलों में बारिश शुरू

उत्तर प्रदेशमें लंबे इंतजार के बाद अब दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार 30 जून 2026 को मानसून ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में दस्तक दे दी है और अगले दो से तीन दिनों के भीतर इसके प्रदेश के अधिकांश इलाकों में सक्रिय होने की संभावना है। मानसून की उत्तरी सीमा इस समय आजमगढ़, अयोध्याऔर बरेली से होकर गुजर रही है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि प्रदेश के शेष हिस्सों में भी जल्द ही अच्छी बारिश शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के शेष भागों के साथ उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अपनी पहुंच बना ली है। इसके अलावा उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों में भी मानसून आगे बढ़ चुका है। मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी और उमस का सामना कर रहे लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून के आगे बढ़ने के कारण प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई के पहले सप्ताह में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में व्यापक वर्षा देखने को मिलेगी। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से काफी राहत मिलेगी।

पूर्व IPS प्रेम प्रकाश ने छोड़ी भाजपा, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी में हुए शामिल

पूर्व IPS प्रेम प्रकाश ने भाजपा छोड़कर सांसद चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) जॉइन कर ली। उन्होंने 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया। सोमवार शाम 6 बजे पार्टी में शामिल होते ही उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में संगठन को मजबूत करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। प्रेम प्रकाश 31 दिसंबर, 2022 को एडीजी, प्रयागराज पद से रिटायर हुए थे। कुछ महीने बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व IPS भाजपा में शामिल हो गए थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया था। हालांकि, भाजपा में उनकी सक्रिय भूमिका देखने को नहीं मिली। कानपुर जोन में तैनाती के दौरान पूर्व IPS के नेतृत्व में करीब 67 एनकाउंटर किए गए थे। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल लाने में भी उनकी प्रमुख भूमिका थी। उस समय प्रेम प्रकाश प्रयागराज में ADG के पद पर थे। दिल्ली के रहने वाले प्रेम प्रकाश 1993 बैच के IPS अफसर थे। बीटेक करने के बाद पुलिस मैनेजमेंट में भी MD (मास्टर इन डिप्लोमा) का कोर्स किया। लंबे प्रशासनिक अनुभव के दौरान मेरठ, आगरा, मुरादाबाद और कानपुर जैसे महत्वपूर्ण जिलों में जिम्मेदार पदों पर काम किया। 12 जुलाई 2009 को लखनऊ में DIG/SSP का चार्ज संभाला था। प्रयागराज में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) के पद पर भी तैनात रहे। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की वजह से उन्हें 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' कहा जाता था।

बाराबंकी में छात्र की मौत के बाद बवाल, हाईवे पर जाम और पथराव

बाराबंकी में 21 साल के पॉलिटेक्निक छात्र की मौत के बाद मंगलवार दोपहर 2 बजे बवाल हो गया। परिजन शव को लखनऊ-बहराइच हाईवे पर रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने जाम खुलवाने के लिए परिजनों पर दबाव डाला तो भीड़ ने पथराव कर दिया। अचानक हुए हमले में रामनगर थाना प्रभारी अरुण प्रताप सिंह के सिर पर पत्थर लगा और वे बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़े। इसके बाद पुलिसकर्मियों को पीछे हटना पड़ा। थाना प्रभारी को घसीटकर हाईवे से हटाया और उन्हें अस्पताल भेजा। बवाल की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंचे। तब फोर्स ने पथराव कर रहे लोगों को खदेड़ा। 2-3 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिसकर्मी शव को अपनी कस्टडी में लेकर अंतिम संस्कार कराने गए हैं। उनके साथ लड़के के परिजन भी मौजूद हैं। हाईवे किनारे और गांव में पुलिस तैनात की गई है। करीब 2 घंटे बाद जाम खुलवाकर वाहन निकलवाए गए। रामनगर कोतवाली क्षेत्र के कटियारा गांव निवासी जितेंद्र चौहान (21 साल) पॉलिटेक्निक छात्र था। सोमवार सुबह 6 बजे जितेंद्र का शव घर के एक कमरे में साड़ी के फंदे से लटका मिला। घरवाले आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मंगलवार को पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद जितेंद्र का शव घर वालों को सौंप दिया। जितेंद्र चौहान के परिजनों का आरोप है कि करीब एक साल से गांव की एक युवती से जितेंद्र का अफेयर था। लड़की के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। पहले भी दोनों परिवारों में झगड़ा हो चुका था।